भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2084

12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

†2084. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ः
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः
श्री बलभद्र माझीः
श्री तापिर गावः
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
श्री मनीष जायसवालः
श्री काली चरण सिंहः
श्री नव चरण माझीः
श्री जुगल किशोरः
श्री नलिन सोरेनः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2025 से अब तक हज़ारीबाग और रामगढ़ ज़िले सहित झारखंड राज्य और ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत एवं पूर्ण की गई परियोजनाओं और उसके अंतर्गत किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है और ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान और जम्मू एवं कश्मीर सहित देश में कितने किसानों को इसका लाभ मिला है;

(ख) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पचास बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और एक सौ खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित 1,920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय हेतु मंत्रिमंडल की स्वीकृति का ब्यौरा क्या है और झारखंड और ओडिशा, विशेषरूप से उक्त जिलों में प्रस्तावित या स्वीकृत इकाइयों/प्रयोगशालाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र सहित देश में अब तक की गई संचयी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इन उपलब्धियों का झारखंड के हज़ारीबाग और रामगढ़ जिलों में कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था, किसानों की आय और रोजगार सृजन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) में "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)" शीर्षक से कोई योजना नहीं है।

हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2017 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है और धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके सहायता प्रदान करने के लिए देश भर से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, जनवरी 2025 से झारखंड और ओडिशा राज्यों में अभी तक किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि, पीएमकेएसवाई की शुरुआत के बाद से, झारखंड में 2 परियोजनाएं और ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र में 6 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें कुल स्वीकृत अनुदान सहायता क्रमशः ₹0.93 करोड़ और ₹23.62 करोड़ है।
31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1607 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 1196 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चालू हो चुकी हैं, जिनसे देश भर में 36,10,782 किसानों को लाभ मिला है, जिनमें ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र के 7,150 किसान, राजस्थान के 1,37,852 किसान और जम्मू और कश्मीर के 53,203 किसान शामिल हैं।

(ख): मंत्रिमंडल ने पीएमकेएसवाई के अंतर्गत ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसमें इसकी घटक योजनाओं के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एफटीएल) की स्थापना के लिए प्रत्येक को ₹500 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमकेएसवाई के लिए मूल परिव्यय ₹4,600 करोड़ में 20% की वृद्धि के रूप में ₹920 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
एमओएफपीआई ने ₹1,000 करोड़ के अतिरिक्त परिव्यय के लिए 27.05.2025 को 50 खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की, जो 28.02.2026 तक खुली रहेगी। अब तक इस ईओआई के अंतर्गत 14 खाद्य विकिरण परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, हालांकि, इनमें से कोई भी परियोजना झारखंड और ओडिशा में स्थित नहीं है। इसके अलावा, 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 21.11.2025 को एक ईओआई जारी की गई थी और यह 10.02.2026 तक खुली रहेगी। आज तक झारखंड या ओडिशा में अतिरिक्त आवंटन के तहत किसी भी खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(ग): प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण से कृषि उपज की मांग बढ़ जाती है, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है, जिससे किसानों को बेहतर कीमतें मिलती हैं और कृषि उपज की लाभप्रदता बढ़ती है। 31.12.2025 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत देश भर में 36,10,782 किसानों को लाभ मिला है और 4,69,403 रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिनमें ओडिशा के नबरंगपुर निर्वाचन क्षेत्र में 4,249 रोजगार के अवसर शामिल हैं। झारखंड के हजारीबाग और रामगढ़ जिलों में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

*****